Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE)

Summary for the month of April 2020

Important events for the month of April 2020 are as follows:

1. The Ministry continued to function during the lock down period, with, a small presence in the office in the initial period, and rest working from home. All officers of JS and above category started functioning from 13th onward, while all officers of DS rank and above, along with one-third staff started functioning from 20th. Various meetings were held over video conferencing as per regular schedule. Proper norms such as social distancing, wearing of masks and regular sanitization of the premises were followed.

2. The lock down period was utilized to finalize the Concept Notes of a number of programmes such as National Apprenticeship Promotion Scheme 2.0, Jan Shikshan Sansthan Scheme 2.0, Entrepreneurship programme, NCVET guidelines, etc. A concept note on a Holistic programme Framework for deepening of Aptitude, Knowledge, Skill, Handiness & Ability of ITI Trainees (DAKSHATA) for modernization and rejuvenation of ITIs has also been prepared and is under consultation process.

3. Online training was continued in ITIs and NSTI, and so far around 10 lakh students are taking online lessons.

4. A Task Force of the Ministry, which was constituted to plan the strategy in light of COVID, has submitted its report on 16/4/2O, with its recommendations in the following areas:

a. Starting Office post lockdown.

b. Ten steps needed to be taken urgently for the growth of the sector.

c. Formation of a Quick Response Team in the Ministry to respond to challenges.

d. Strategies for Framing Policies which were facing obstacles.

e. Whether Units can be started where all personnel stay in the Campus itself.

f. Preparation of Business Plan for Sector Players to start functioning.

g. Steps that Ministries can take for encouraging Make in India and to secure and increase India's share in World exports.

5. Ministry prepared an action plan for taking up specific skilling activities in light of COVID and made a presentation in PMO, in which the Principal Secretary, Principal Advisor and the Advisors participated, along with CEO, NITI Aayog and other officials of PMO. Consequent to this a proposal of Rs 1550 crores, for carrying out three activities was sent to PMO for inclusion in special package.

6. While the Ministry had made available all campuses of NSTI/ ITI for isolation/ quarantine facilities, as per reports received so far, 12 NSTI/ ITI buildings have been requisitioned by the District Authorities in light of CORONA. Similarly PMKVY training partners have also provided their premises for such facilities, including for a temporary hospital.

7. Institutions under MSDE ecosystem have been active in manufacture of masks and hand sanitizers. While the JSSs have so far made more than 16 lakh masks, the ITI system has built more than 7 lakh masks.

8. Many of the ITIs/ NSTI have indulged in innovative design and manufacturing to assist the fight against COVID. Some of them are:

i) Service robot and telepresentation robot by ITI Cuttack.

ii) Hands free, walk in mass collection of samples for COVID testing by ITI Cuttack.

iii)Govt ITI Berhampur, Odisha designed and developed "Aerosol Box" which tightly shields health care providers face from patient's face.

iv)NSTI Ludhiana has prepared an Aero Blaster Machine and handed it over to District Administration for sanitizing the city.

v) NSTI Mumbai developed pedal based (hands free) hand sanitizing system and installed in local police station.

9. A final demonstration of the portal on Skill Management Information System (SMIS) was held on 3O/4/2020, under which data of around a crore skilled workers, competency wise and

location wise, would be provided to employers at the click of the mouse. The portal is likely to be launched in June 2020.

10. Under the SANKALP scheme, all India capacity building training was conducted for officials of State Skill Development Mission on 29th April 2020, through Video Conferencing.

11. Under the STRIVE scheme, 6 ITIs signed a tripartite agreement for participating in the programme, taking the total number of such ITIs to 250. The draft Recruitment, Training and Career Progression Policy document for Craft instructors/Trainers of Industrial Training Institutes (ITIs) was also prepared and shared for consultation in this period. A video-conference meeting with World Bank Team was held on 15th April 2020 to discuss on way forward on restructuring of STRIVE in wake of COVID 19.

12. Hon'ble Minister and Secretary interacted through video conferencing with select ITIs and JSSes to review their work and assess the activities undertaken by them during lockdown.

13. Jan Shikshan Sansthan (JSS) Scheme, which was coming to a close on 31.3.2020, was given extension till 31.3.2021 or till date the recommendations of 15th Finance Commission come into effect or till further orders, whichever is earlier.

14. A meeting was held with Secretary WCD, and CEO, NSDC over Video Conferencing, to take up skilling initiatives for that Ministry, preferably on a digital platform.

15. As per directions of Department of Expenditure, the expenditure for month of April was maintained at 5%. Further, detail quarterly limits for each head of expenditure has been fixed, so as to retain the overall expenditure at 15% for the first quarter.

*****

<u>कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)</u>

<u>अप्रैल 2020 माह का मासिक सारांश</u>

अप्रैल 2020 माह के महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नलिखित है:

1. इसमंत्रालय ने लॉकडाउन अवधि के दौरान कार्य करनाजारी रखा, प्रारंभिक अवधि में कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति कम राखी गई तथा शेष कर्मचारियों ने घर पर रहकर काम करना जारी रखा। संयुक्त सचिव और उससे ऊपर की श्रेणी के सभी अधिकारियों ने लॉकडाउन के 13वें दिन से तथा उप-सचिव और उससे ऊपर की श्रेणी के सभी अधिकारियों ने एक-तिहाई कर्मचारियों के साथ लॉकडान के 20 वें दिन से काम करना शुरू कर दिया था। नियमित अनुसूचीके अनुसार वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से विभिन्न बैठकें आयोजित की गई। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने और कार्यालयपरिसर कीनियमित स्वच्छता जैसे उचित मानदंडों का पालन किया गया।

2. लॉकडाउन अवधि का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम 2.0, जन शिक्षण संस्थान स्कीम 2.0, उद्यमशीलता कार्यक्रम, एनसीवीईटी दिशा-निर्देशों आदि जैसे अनेक कार्क्रमों से संबंधित कई अवधारणा नोट को अंतिम रूप दिया गया। आईटीआई के आधुनिकीकरण और कायाकल्प के लिए आईटीआई शिक्षुओं की अभिक्षमता, ज्ञान, कौशल, हैण्डीनेस और क्षमता को गहन करने के लिएसमग्र कार्यक्रम ढाँचे(दक्षता)पर एक अवधारणा नोट भी तैयार किया गया है और इस पर परामर्श चल रहा है।

3. आईटीआई और एनएसटीआई में ऑनलाइन प्रशिक्षण जारी रखा गया, और अब तक लगभग 10 लाख छात्र ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं।

4. मंत्रालय का एक कार्यबल,जिसका गठन कोविड को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजना बनाने के लिए किया गया था, ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.04.20 को अपनी सिफारिशों सहित प्रस्तुत करदीहै जो निम्नलिखित है:

क. लॉकडाउन के पश्चात कार्यालय को प्रारंभ करना।
ख. क्षेत्र की वृद्धि के लिए तत्कालिक रूप से 10 कदम उठाने की आवश्यकता है।
ग. चुनौतियों का सामना करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन।
घ. उननीतियों को तैयार करने के लिए रणनीतियां जिनमेंबाधा उत्पन्न हो गई थी।
ङ. उनइकाईयों को शुरू कियाजा सकताहै, जिनकेसभी कर्मी परिसर में ही रहते हैं।
च. कार्य प्रारंभ करने के लिए सेक्टर प्लेयर्स हेतु व्यापारिक योजना तैयार करना।
छ. ऐसे उपाय जो मंत्रालय में मेक-इन-इंडिया को प्रोत्साहित करने तथा विश्व निर्यात में भारत के हिस्से को सुरक्षित करने और बढ़ाने के लिए किए जा सकते हैं।

5. मंत्रालय ने कोविड के मद्देनजर, विशिष्ट कुशल गतिविधियां करने हेतु एक कार्ययोजना तैयार की और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक प्रस्तुतीकरण दिया, जिसमें प्रधान सचिव, प्रधान सलाहकारों सहित नीति आयोग के सीईओ और प्रधानमंत्री कार्यालय के अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया। 1550 करोड़ रुपए के इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप, तीन गतिविधियों को विशेष पैकेज में शामिल करने हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया।

6. मंत्रालय ने एनएसटीआई/आईटीआई के सभी परिसरों को आईसोलेशन/क्वारनटाईन की सुविधाओं के लिए उपलब्ध कराया, जबकिअब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, कोरोना के मद्देनजर जिला अधिकारियों द्वारा12 एनएसटीआई/आईटीआई भवनों की मांग की गई थी। इसी प्रकार, पीएमकेवीवाई के प्रशिक्षण भागीदारों ने भी इस तरह की सुविधाओं के लिए अपना परिसर उपलब्ध कराया है, जिसमें एक अस्थायी अस्पताल भी शामिल है।

7. एमएसडीई इकोसिस्टम के अंतर्गत, संस्थाएं मॉस्क और हैंड सेनिटाइजर के निर्माण में सक्रिय है। जेएसएस ने अब तक 16 लाख से अधिक मास्क बनाएं है, जबकि आईटीआई तंत्रने 7 लाख से अधिक मास्क तैयार किए हैं।

8. कोविड के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने हेतु नवोन्मेषी निर्माण तथा विनिर्माण में कई आईटीआई/एनएसटीआई संलग्नहैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(i) आईटीआई, कटक द्वारा रोबोट सेवा तथा टेलिप्रेजेन्टेशन रोबोट।
(ii) आईटीआई, कटक द्वारा कोविड परीक्षण के लिए नमूनों का हैंड्स-फ्री, वॉक-इन मास कलैक्शन।
(iii) सरकारी आईटीआई बेरहामपुर, ओडिशा ने 'एयरोसोल बॉक्स'निर्मित तथा विकसित किया है जो काफी मजबूत स्वास्थ्य देखरेख प्रदाता है, जिसमें से रोगी को होकर जाना पड़ता है।
(iv) एनएसटीआई, लुधियाना ने 'एयरो ब्लास्टर'मशीन तैयार की है और इसे शहर को साफ करने हेतु जिला-प्रशासन को सौंप दिया गयाहै।
(v) एनएसटीआई, मुंबई ने पैडल आधारित हैंड सेनिटाइजिंग सिस्टम विकसित किया है और इसेस्थानीय पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गयाहै।

9. कौशल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एसएमआईएस) पोर्टल का अंतिम प्रदर्शन दिनांक 30.04.2020 को आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत सामर्थ्यता-वार और स्थान-वार लगभग 1 करोड़ कुशल श्रमिकों केआंकड़े माउस के एक क्लिक पर नियोजकों को उपलब्धहोंगे। इस पोर्टल को जून 2020 में प्रारंभ किए जाने की संभावना है।

10. संकल्प योजना के तहत, वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 अप्रैल, 2020 को राज्य कौशल विकास मिशन के अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।

11. स्ट्राइव योजना के तहत, 6 आईटीआई ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, ऐसे आईटीआई की कुल संख्या 250 है। प्रारूप निर्देश, शिल्प प्रशिक्षकों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण तथा कैरियर प्रगति नीति दस्तावेज इसी अवधि में परामर्श के लिए तैयार और साझा किया गया था। कोविड-19 के मद्देनजर, स्ट्राइव के पुनर्गठन पर आगे की चर्चा के लिए 15 अप्रैल, 2020 को विश्व बैंक दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एकबैठक आयोजित की गई थी।

12. माननीय मंत्री और सचिव ने लॉक डाउन के दौरान कार्य की समीक्षा करने और उनके द्वारा की गई गतिविधियों का आकलन करने हेतु चुनिंदा आईटीआई और जेएसएस के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात-चीत की गई।

13. जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम, जो 31.03.2020 को समाप्त होने वाली थी, उसे31.03.2021 तक या 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू होने तक या अगले आदेश तक; जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।

14. सम्बंधित मंत्रालय के लिए कौशल विकास पहल शुरू करने हेतु सचिव, महिला और बाल विकास मंत्रालयऔर सीईओ, एनएसडीसी के साथ अधिमानत:डिजिटल मंच परएक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक आयोजित की गई थी।

15. व्यय विभाग के निर्देशानुसार अप्रैल महीने के लिए व्यय 5% रखा गया था। इसके अतिरिक्त, व्यय के प्रत्येक शीर्ष के लिए त्रैमासिक सीमा तय की गई है, इसलिए पहली तिमाही के लिए व्यय को 15% पर बनाए रखना है।

*****